आकाशवाणी केन्द्र शिमला

13.12.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने सीआरआईएफ के तहत 3 सौ 50 करोड़ रुपये मंजूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये धनराशि प्रदेश में सड़क सम्पर्क में सुधार और राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। लोक निर्माण मंत्री ने भुभूजोत में सुरंग के साथ घटासनी, शिल्हा–बधानी–भुभूजोत–कुल्लू तक एक वैकल्पिक सड़क बनाने और भारत सेतु परियोजना के तहत कांगड़ा व हमीरपुर ज़िलों को जोड़ने वाले बसंतीपतन व खीरी के बीच ब्यास नदी पर एक सौ 25 करोड़ 57 लाख रुपये के डबल लेन पुल के निर्माण को स्वीकृति देने का आग्रह किया। नितिन गडकरी ने राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

अग्निहोत्री

उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उना जिले के रामपुर में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय का आज उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग का कार्यालय खुलने से वंचितों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में नियोजित विकास पर बल देते हुए उना, हमीरपुर और बद्दी को नगर निगम बनाया जा रहा है जिससे इन क्षेत्रों में विकास की गति और तेज होगी। उप–मुख्यमंत्री ने उना जिले में अवैध खनन चिट्टा और पेड़ कटान पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार युवा हितैषी है और विभिन्न पदों के लंबित परीक्षा परिणाम एक महीने के भीतर घोषित कर दिए जाएंगे। अग्निहोत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में पेपर बिकते थे लेकिन मौजूदा सरकार पूरी पारदर्शिता से कार्य कर रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं को एचआरटीसी को बदनाम करने की ओछी राजनीति न करने की

सलाह दी है। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एचआरटीसी को पैंशन की अदायगी के लिए साढ़े 67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इंदु गोस्वामी

केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा विकसित की जा रही 8 सौ मैगावाट क्षमता की पार्वती जल विद्युत परियोजना के दूसरे चरण का कार्य मार्च 2025 में पूरा कर लिया जायेगा। संसद में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस परियोजना में आंशिक रूप से विद्युत उत्पादन सितम्बर 2018 से शुरू हो गया है और अब तक परियोजना से एक हजार एक सौ 29 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया जा चूका है। इस बीच सांसद इंदु गोस्वामी के एक अन्य सवाल के जवाब में केन्द्रीय पर्यावरण व वन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह बताया कि हिमाचल सरकार द्वारा प्रदान की गई वार्षिक योजना के तहत केन्द्र सरकार ने सिरमौर जिला में स्थानीय नागरिकों को हाथियों के उपद्रव से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और एलीफैंट के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 के दौरान 19 लाख 61 हजार रूपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की।

जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार प्रदेश के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है, इसलिए विधानसभा का सत्र महज चार दिन का रखा है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समय बढ़ाए जाने की सरकार से मांग की है, ताकि इसमें जनता से जुड़े मुद्दों पर बात हो सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की व्यवस्ताओं के कारण और सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए विधानसभा सत्र आयोजित करना निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में सरकार की नाकामियों की वजह से मुद्दों की भरमार है और हर वर्ग सरकार की झूठी गारंटियों के कारण ठगा महसूस कर रहे हैं।

राजीव भारद्वाज

केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने ऊना जिला में प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ चिन्तपूर्णी मन्दिर को प्रशाद योजना के तहत धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए चुना है। लोकसभा में सांसद राजीव भारद्वाज के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि योजना के तहत माँ चिन्तपूर्णी मन्दिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर ढांचा विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस धार्मिक स्थल के सम्पूर्ण विकास के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को अभी तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं सौंपी है। राजीव भारद्वाज के एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि युवा सहकार योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की किसी भी सहकारी समिति का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि युवा सहकार योजना के अन्तर्गत तीन महीने से कार्यरत युवा उद्यमी सहकारी समितियों को पांच साल की अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

बैठक

मंडी ज़िला में इस वित्त वर्ष में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर एक सौ 82 करोड़ 59 लाख 48 हजार चार सौ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विधायक व जिला कल्याण समिति के अध्यक्ष चन्द्रशेखर ने आज मंडी में आयोजित समिति की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में इस वर्ष तीसरी तिमाही तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 4 हजार 7 सौ 54 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं।

————————————————————